संख्या-45/1140/एक-1-2015-5(72)/2014

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 06 जुलाई, 2015

विषय:- मेसर्स मंगलौर मिनरल्स प्रा0लि0 द्वारा बिना पूर्वानुमति क्रय की गयी 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के संक्रमण को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4962/डीएलआरसी, दिनाँक 11.08.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल मेसर्स मंगलौर मिनरल्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम असवॉ परगना व तहसील बारा जनपद इलाहाबाद में क्रय की गयी भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-154 (3) के अधीन सिल्का सैण्ड प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु नियत सीमा से अधिक अर्थात 12.50 एकड़ से अधिक क्रय की गई कुल भूमि 20.301 हेक्टेअर के विनियमितीकरण करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) मेसर्स मंगलौर मिनरल्स प्रा0लि0 को सिल्का सैण्ड प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना नियत सीमा से अधिक क्रय की गई भूमि पर अर्थदण्ड की राशि, स्टाम्प शुल्क की गणना के लिये मूल्यांकित धनराशि के 25 प्रतिशत के समान होगी।

(2) उपरोक्त संस्था द्वारा उतनी ही भूमि की अनुमति अनुमन्य होगी जो उसके लिये आवश्यक हो। आवश्यकता का निर्धारण सम्बन्धित औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी।

(3) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 तथा अन्य संगत शासनादेशों/नियमों के अधीन की जायेगी।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन हेतु किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। मानक से अधिक भूमि होने की स्थिति में पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा जिसके लिये भूमि क्रय की गई है। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग

shasnadesh.up.nic.in

-2-

किये जाने पर शासन द्वारा उपर्युक्त अनुमति निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित कर ली जायेगी।

(6) क्रय की गई भूमि अधिकृत संस्था के नाम होगी।

(7) उक्त भूमि धारित करने हेतु किया गया प्रत्येक संक्रमण प्रचलित अधिनियमों, नियमों, विनियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अधीन होगा।

(8) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में राजस्व विभाग की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं करेगा।

(9) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 12.50 एकड़ से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(10) उक्त संस्था के लिये ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि अनुमन्य होगी।

(11) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित/सीलिंग की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव अलग से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं जिलाधिकारी, इलाहाबाद उपर्युक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-1140(1)/एक-1-2015-5(72)/2014 तद दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

shasnadesh up.nic.in

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in